



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 जून, 2004/5 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 18 जून, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-4347.—यह कि श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, का ध्यान हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ग) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है:—

(ग) यदि उसके दो से अधिक सन्तानें हैं, परन्तु खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जिसमें यथास्थिति हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तानें हैं, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122(1) के खण्ड (ग) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व दो जीवित सन्तानें हैं और खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़ ने अपने पत्र संख्या डी० बी० ना० (पंच)/2004-349, दिनांक 18-5-2004 द्वारा सूचित किया है कि उक्त (उप-प्रधान) के एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान दिनांक 13-3-2004 को हुई है। जिसके फलस्वरूप श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड नालागढ़, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ग) के प्रावधान अनुसार (उप-प्रधान) पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः श्री जागीर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, खण्ड विकास नालागढ़ को निर्देश देते हैं कि वह नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करे कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल लाई जाए।

सोलन, 18 जून, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-4348-53.—यह कि श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड संख्या 3, विकास खण्ड नालागढ़ का ध्यान हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ग) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है :—

(ग) यदि उसके दो से अधिक सन्तान है, परन्तु खण्ड (ग) के अधीन निरहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जिससे यथास्थिति हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तानें हैं, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।

अतः क्योंकि हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122(1) के खण्ड (ग) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है।

यह कि श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं० 5 की उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व दो जीवित सन्तानें हैं, और खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़ ने अपने पत्र संख्या डी० बी० ना० (पंच)/2004-302, दिनांक 7-5-2004 द्वारा सूचित किया है कि उक्त सदस्या के एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान दिनांक 26-12-2003 को हुई है। जिसके फलस्वरूप श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं० 5, विकास खण्ड नालागढ़, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ग) के प्रावधान अनुसार सदस्या पद पर बने रहने के अयोग्य हो गई है।

अतः श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सौर, वार्ड नं० 5, खण्ड विकास नालागढ़ को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

सोलन, 18 जून, 2004

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-4354-59.—यह कि श्रीमती निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बवासली, वार्ड नं० 7, विकास खण्ड नालागढ़, का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ग) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है।

(ग) यदि उसके दो से अधिक सन्तान है, परन्तु खण्ड (ग) के अधीन निरहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधित) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 (1) के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है।

यह कि श्रीमति निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं० 7, की उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व दो जीवित सन्तान है, और खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़, ने अपने पत्र संख्या डी0बी0नार0 (पंच) 2004-279, दिनांक 5-5-2004 द्वारा सूचित किया है कि उक्त सदस्या के एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान दिनांक 9-12-2003 को हुई है। जिसके फलस्वरूप श्रीमति निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं० 07, विकास खण्ड नालागढ़, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः श्रीमति निर्मला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं० 7, खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़ को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस नोटिस के प्राप्त के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए।

सोलन, 18 जून, 2004

संख्या एस0एल0एन0 11-106 (डब)/73-4369-73.—यह कि ग्राम पंचायत बखालग, की दिनांक 6-4-2004 की बैठक जो उप-प्रधान श्री नरेश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है, के प्रस्ताव संख्या-2 में पारित करके यह सूचित किया गया कि प्रधान ग्राम पंचायत बखालग, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की निम्न-लिखित बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं जिससे पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है और पंचायत के लोग आहत हो रहे हैं:

दिनांक 8-3-2004 ग्राम पंचायत की बैठक।

दिनांक 26-3-2004 ग्राम पंचायत की बैठक।

दिनांक 6-4-2004 ग्राम पंचायत की बैठक।

दिनांक 4-4-2004 ग्राम सभा की बैठक।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत निरीक्षक द्वारा दिनांक 22-5-2004 को पंचायत के रिकार्ड से कर ली गई है और आरोप सही पाया गया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) में प्रावधान है कि:—

यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी निर्वाचित किए जाने पर :

(ख) पंचायत या इसकी समितियों की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना छः मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है, तो वह उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा।

अतः इससे पहले कि आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये, आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।

सोलन, 19 जून, 2004

संख्या सोलन-4-7(पंच)/83-4379.—खण्ड विकास अधिकारी, सोलन ने अपने पत्र संख्या सोलन 1 (18) 99-पंच-1160, दिनांक 19-5-2004 के साथ ग्राम पंचायत बसाल, के प्रस्ताव संख्या 7, दिनांक 5-4-2004 की प्रति इस कार्यालय को भेज कर सूचित किया है कि श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल निम्न-लिखित ग्राहक बैठकों में पंचायत को सूचित किए बिना लगातार अनुपस्थित रहा है। (दिनांक 23-8-2003, 5-9-2003, 22-9-2003, 3-10-2003, 22-10-2003, 5-12-2003, 22-12-2003 तथा 22-1-2004) इस सदस्य की अनुपस्थिति को देखते हुए उसके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी अनिवार्य हो गई है।

अतः श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत बसाल, वार्ड नं० 6 को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि वह अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यत समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, और उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सोलन, 19 जून, 2004

संख्या सोलन-4-31(पंच)/76-43-84.—यह कि ग्राम पंचायत धरोट द्वारा करावाए गए निर्माण लिक रोड चम्बाघाट से उच्च पाठशाला गुगाघाट करयाली बारे प्राप्त शिकायत की जांच करने पर खण्ड विकास अधिकारी, सोलन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पाया गया है कि निर्माण लिक रोड चम्बाघाट से उच्च पाठशाला गुगाघाट, करियाली-II हेतु मु० 50,000/- रु० स्वीकृत किया गया था। जिसमें से पंचायत को मु० 46,011/- रु० की अदायगी की गई थी। कार्य का मूल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा मु० 46,011/- रु० का आंका गया है, जबकि पंचायत के रिकार्ड अनुसार इस कार्य पर मु० 49,470/- रु० का व्यय दर्ज रोकड़ डाला गया है। जिसमें मु० 3,459/- रु० का मूल्यांकन से अधिक व्यय डाला गया है। इस प्रकार कार्य पर मु० 3,459/- रु० अधिक व्यय डाल कर पंचायत निधि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरदायी है।

अतः इससे पूर्व कि प्रधान, ग्राम पंचायत धरोट, के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि वह इस बारे अपना स्पष्टीकरण इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त, सोलन,
जिला सोलन (हि० प्र०)।